बनना है तो मुख्यमंत्री

छः में से चार तो बिक गये, पर वे नहीं बिके। कहते हैं, कीमत बेहिसाब मिल रही थी, फ़िर भी नहीं बिके। बापू ने समझाया, यार-दोस्तों ने समझाया, पर ये जरा भी अपने स्टैंड से हिलने को तैयार नहीं। वैसे अगर ये बिकते तो इसे बिकना नहीं, दो बिछुड़े सहोदरों का पुनर्मिलन कहा जाता। लेकिन नहीं।

इतने दिनों तक, इतना अधिक पैसा खर्च कर जो मजमा जुटाते रहे और अपनी एक अलग 'छवि' बनाते रहे, ये ही दिन देखने के लिए? उनके समर्थक क्या कहेंगे?

क्या उन्हें सत्तालोलुप नहीं कहा जायेगा? पर सवाल है, राजनीति के मैदान में सत्तालोलुप कौन नहीं है? क्या मैडम जी सत्तालोलुप नहीं हैं? अगर नहीं हैं तो यह समय उनके काशीवास का आ गया है। मैडम जी के यहां से भी बुलावे का संकेत आया।

मंत्री पद देने की बात थी। राज्य में उपमुख्यमंत्री पद दिया जा रहा था। पर उपमुख्यमंत्री पद परिवार में जमता नहीं। इस पद पर बैठने के बाद क्या 'बुरा' हाल हुआ भाई साब का। पर अपन लक्ष्य पर अर्जुन की तरह निगाह रखते हैं। लक्ष्य को बेध कर रखना है। तांत्रिकों का कहना है, हुड्डा सरकार पांच साल नहीं चलेगी और न ही मनमोहन सरकार। देश की राजनीति पर बड़ी विपत्ति आने वाली है। ऐसी स्थिति के लिए तैयार रहना है। अपन को मुख्यमंत्री ही बनना है।

मामला सेट हो गया

मंत्रिमंडल बनाना भी आसान काम नहीं है। हुड्डा साहब बड़ी मुसीबत में फंसे रहे। आख़िरकार किसी तरह किसी को समझा कर, किसी के आगे रिरिया कर, एक के पीछे दूसरे को गालियां देकर जैसे-तैसे मंत्रिमंडल बनाया। अब सभी तो मंत्री बन नहीं सकते।

लेकिन टिकट खरीदने से लेकर, प्रचार करने, कार्यकर्ताओं की हर मांग पूरी करने में जितने खर्च हो गये, वह माल अगर सूद समेत वापस नहीं आया तो फ़िर इस राजनीति का फ़ायदा ही क्या है। इससे अच्छा तो कबाड़ की एक दुकान खोल कर चोरी का माल खरीदते और बेचते।

हुड्डा पर ये ज़ोरदार दबाव बना रहे थे। तब तो मंत्रिमंडल बनाने में इतनी देर हो गई। इसका बहुत ही ग़लत संदेश मैडम जी के पास जा रहा था। उन्होंने स्पष्ट आदेश दे रखा था कि जिस भाव मिल रहे हैं, खरीद लो।

सच है, खरीदे बिना दूसरा कोई चारा नहीं था। फ़िर जितने में खरीदूं, उसका डेढ़ गुणा अथवा दो गुणा फ़ायदा स्वयं ही क्यों न ले लूं?

बस हुड्डा ने निर्दलीयों और हजकां में अपने 'विश्वसनीय' दूत दौड़ाये। हजकां वाले तैयार थे, बल्कि देर होने से असंतुष्ट भी होते जाते रहे थे। निर्दलीय विधायकों में भी छटपटाहट थी। मंत्री बनने की। कुछ तो बनेंगे ही। वैसे ज़्यादा मोलभाव करने की जरूरत नहीं पड़ी। मामला सेट हो गया। मैडम जी भी संतुष्ट हैं।

गपशप

सूचना के अधिकार से तंग

मुश्किलें कम नहीं हैं। पिछले दिनों इतने शिलान्यास कर डाले कि बस पूछो मत। वैसे जनता शिलान्यासों से कोई खास प्रभावित नहीं होती। लोग़ों के पास खुद के अपने इतने झमेले होते हैं कि वे शिलान्यासों का हिसाब रखेंगे? वे तो बस रोटी-दाल की जुगाड़ में ही परेशान रहते हैं।

पर बुद्धिजीवी, पत्रकार और पढ़-लिख कर निठल्ले बैठे लोग़ों से थोड़ी परेशानी महसूस होती है। तरह-तरह के मुद्दे उठायेंगे। इस निर्माण कार्य का शिलान्यास हुए इतने दिन बीत गये, काम कब शुरू होगा, होगा भी या नहीं होगा?

इसी तरह के सवाल रहते हैं। फ़िर मीडिया वाले भी खोज़ी पत्रकारिता के चक्कर में कोई न कोई अभियान चलाते ही रहते हैं। खास बात यह है कि सबों का मुंह पैसे से बंद नहीं किया जा सकता। पढ़-लिख कर निठल्ले बैठे लोग़ों को और कुछ नहीं सूझता तो बस सूचना के अधिकर के तहत सूचनायें मांगने लगते हैं। ये इतनी सूचना मांगते हैं और ऐसी-ऐसी सूचना मांगते हैं कि हमारे अफ़सर परेशान हो जाते हैं।

काम की गति धीमी हो जाती है और गड़े मुर्दों को उखाड़ने का काम शुरू हो जाता है। कोई सूचना न मिले तो संबंधित विभाग का अफ़सर बेहाल। सूचना तो चाहिए, नहीं तो अपील होगी और दंड मिलेगा।

सूचना का अधिकार सचमुच एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। ये तो सरकार ने सरकारी और जनहित से जुड़ी सूचनाओं को मांगने का अधिकार दिया है, कहीं हर तरह की सूचना मांगने का अधिकार दे देते तो सूचना चाहने वाले ऐसी भी सूचना मांगने लगते - फलां अधिकारी अपनी बीवी के साथ माह में कितनी रातें बिताते हैं? शेष रातें वे कहां बिताते हैं आदि-आदि।

सरकार पांच वर्ष चलेगी?

'सरकार पूरे पांच वर्ष तक चलेगी।' जब बनी है तो चलेगी ही। फ़िर यह कहने का मतलब क्या है? क्या कोई पूछ रहा है कि सरकार कितने दिनों तक चलेगी? बहुमत मिला नहीं। उसका 'जुगाड़' किया गया। बस इसी जुगाड़ को लेकर मैडम जी आश्वस्त नहीं हैं। और इन्होंने भी नाक में दम कर रखा है। सभी मंत्री पद ही पाना चाहते हैं।

भूल गये कि नकदी देकर इन्हें खरीदा गया है। अरे भाई, विधायकों के खाने-कमाने के ज़रिये कम नहीं होते। बस आंखें खुली रहनी चाहिए। अपने इलाके में चक्कर काट आओ और खोल दो पत्ते। कहीं नौकरी देने का ढोल बजा दो तो कहीं कह दो पुलिस की भर्तियां निकलने वाली है।

कह कर भाग चलो। कोई कहां तक पीछा करेगा? साल-छः महीने भटकाओ। फ़िर कुछ नये पत्ते खोलो। इसी तरह समय बीतता जायेगा। पर ये समझते नहीं। हर बार, एक ही बात-सरकार पूरे पांच वर्ष चलेगी? इनसे विरोधी भी मजे लेते हैं- क्यों भाई, सरकार पांच वर्ष पूरे चलेगी? तब तो ये कहते हैं- हां, चलेगी। पर तुरंत हमारा सिर खाने आ जाते हैं कि सरकार पांच वर्ष चलेगी या नहीं? हम तो इनसे तंग आ गये हैं जी।

मंत्री पद की आस

इस बार मंत्री बनने की पूरी आस थी। आस थी तो गलत नहीं थी। पूरे पांच वर्ष तक सरकार को चलाने में पहिये की भूमिका निभाती रही। केवल एक बार असंतुष्ट जनता से पानी में डूबने-उतराने वाले मामले में पिटने की नौबत आई थी। गार्ड सजग नहीं था, इसलिए एक-आध हाथ लग गये।

वैसे, इस मामले को मीडिया ने हवा नहीं दिया। शहर के पत्रकारों से अच्छी सेटिंग है, फ़िर भी खिलाना और पिलाना पड़ता है। बहुत तो ऐसे हैं जो खाते तो नहीं, मगर पीते जबरदस्त हैं और नशे में पूरी तरह बहक कर हाय-हाय करने लगते हैं।

खैर, अब तक बेदाग कैरियर रहा हमारा, पर इस बांगड़ ने मंत्री नहीं बनाया। वही संसदीय सचिव। फ़िर मैंने भी ठेंगा दिखा दिया। चाहते हैं कि दूसरों का सब लूट-खसूट ले और अपने पल्ले से एक चवन्नी भी न जाये। थूक चाटने को कहो तो इसके लिए भी तैयार। पर मंत्री नहीं बनायेंगे। कहते हैं, इस बार 'स्वतंत्र' विधायकों को समर्थन की एवज में मंत्री बनने की स्वतंत्रता मिली है। तुझे अगली बार बनाऊंगा। पर ऊपर वाले की दया हुई तो अगली बार कहीं केंद्र में ही राज्य मंत्री न बनूं?

साइकिल की सवारी

मुलायम सिंह ने सख़्त रुख दिखाते हुए कल्याण सिंह का 'कल्याण' कर दिया। यह पूछने पर कि उन्हें पार्टी में बुलायेंगे, तीन बार 'नहीं' कहा कि और इस सवाल पर कि अगर वे खुद आना चाहें तब फ़िर वही तीन बार 'नहीं' दुहरा दिया। साफ़-साफ़ कहा कि उन्हें तो वे भाजपा को कमज़ोर करने के लिये लाये थे। उन्होंने यह भी कहा था कि कल्याण सिंह उनकी पार्टी में कभी थे भी नहीं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री वही होंगे।

खैर, मुख्यमंत्री बनें या नहीं बनें, यह आगे की बात है, अभी प्रश्न यह है कि कल्याण सिंह से उन्होंने मुलायम से साइकिल वापस क्यों ले ली? इस सवाल पर अंदर के कुछ जानकार बताते हैं कि कल्याण ने कुसुम राय को भी अपनी साइकिल पर बिठा लिया था। और सिर्फ़ बिठा ही नहीं लिया था, बल्कि उनके लिये एक अलग से खास साइकिल बनवाने की फिराक में थे। 'धरतीपुत्र' मुलायम के लिये यह बर्दाश्त से बाहर की बात थी। इसलिए उन्होंने कल्याण को पटकनी दे दी।

चार्ज सौंपने के लिए तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर ओमप्रकाश

होडल (डी.सी. चौधरी) लगता है कि तहसील होडल में कार्यरत कर्मचारियों की जिद के आगे एस.डी.एम. के आदेश भी कोई मायने नही रखते हैं। जाहिर है कि ऐसे हठी कर्मचारियों की जिद के आगे तहसीलदार की तो औकात ही क्या है। मामले के अनुसार होडल तहसील कार्यालय में होडल के तहसीलदार के रीडर के रूप में कार्यरत ओमप्रकाश नामक क्लर्क अगस्त माह में स्थानांतरण होने के बावजूद भी आज तक अपना चार्ज सौंपने के लिए होडल तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने के लिए मजबूर है।

उक्त लिपिक अपना चार्ज सौंपने के लिए कैथल से होडल तक बार-बार लंबा सफर तय करता है। इसके बाद भी उसे निराशा ही हाथ लगी है व एस.डी.एम. होडल प्रदीप गोदारा को लिखित शिकायत देकर भी अवगत करवा चुका है परंतु होडल तहसील में कार्यरत कर्मचारियों को उपमंडल अधिकारी के आदेशों की भी कोई परवाह नहीं है जबकि उपमंडल अधिकारी द्वारा कार्यालय में कार्यरत रीडर की कुर्सी पर बैठे हुए एक लिपिक को मौखिक रूप से चार्ज लेने के लिए कहने के बावजूद भी वह लिपिक अपनी शर्तो पर ही उक्त लिपिक से चार्ज संभालने के लिए अपनी जिद पर अड़ा हुआ है।

मामले के अनुसार होडल के तहसीलदार के रीडर के रूप में कार्यरत कर्मचारी का तबादला लगभग 3 माह पूर्व होडल से उपायुक्त कार्यालय कैथल में हो चुका है। जबकि उक्त कर्मचारी ने होडल से तबादला होने के तुरंत बाद सरकारी आदेशों की पालना करते हुए उपायुक्त कार्यालय कैथल में अपना कार्यभार संभाल लिया और निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य निभा रहा है। उक्त लिपिक अपना तबादला होने के पश्चात अपना चार्ज देने के लिए कई बार कैथल से होडल के तहसील कार्यालय में धक्के खाने के बावजूद भी तहसील कार्यालय में कार्यरत कोई भी कर्मचारी उक्त लिपिक से चार्ज लेने को तैयार नहीं है। होडल से कैथल तबादला होकर जा चुके लिपिक ने होडल के तहसीलदार को भी मामले से अवगत करवा दिया है।

तहसीलदार के आदेशों के बावजूद भी धक्के खा रहे लिपिक को कोई राहत नहीं मिली है।

थकहार कर उसने अपने चार्ज देने के मामले को लेकर होडल के एस.डी.एम. प्रदीप गोदारा को लिखित रूप से सूचित किया था और एस.डी.एम. ने मौखिक रूप से एक लिपिक को चार्ज लेने के बारे में निर्देश दिए थे लेकिन उक्त लिपिक ने एस.डी.एम. के आदेशों को भी हवा में उड़ा दिया है। परेशान हाल कर्मचारी ओम प्रकाश ने उक्त मामले की शिकायत जिला उपायुक्त पलवल,आयुक्त मण्डल गुड़गांव एवं वित्तायुक्त राजस्व एवं आपदा प्रबंधन चंडीगढ़ को भी लिखित रूप से सूचित कर दिया है। अब देखना है कि पीड़ित की समस्या को हल करने में अधिकारीगण कितना समय और लगाते हैं।

डाकघर में पोस्टमास्टर की नियुक्ति नहीं

होडल (म.मो) 14 सितम्बर 2009 को होडल के डाकखाने का उदघाटन कर उसे चुनिंदा डाकघरों में शमिल किया गया था और उदघाटन से करीब10 दिन पूर्व ही डाकघर के पोस्टमास्टर का तबादला करके उन्हें पलवल स्थानांतरित कर दिया गया था।

तबसे लेकर आज तक होडल का उक्त आधुनिक डाकखाना पोस्टमास्टर की बाट जोह रहा है। डाकखाने में करीब 3 महीनों से पोस्टमास्टर की खाली पड़ी कुर्सी अधिकारी के आने का इंतजार कर रही है। लेकिन विभाग द्वारा करीब 3 माह बीतने बाद अभी तक यहां पर पोस्टमास्टर की नियुक्ति नहीं की गई है। उदघाटन के समय डाकखाने में बिजली की आपूर्ति निर्बाध रूप से चालू रखने के लिए विभाग द्वारा लगाया गया जेनरेटर मात्र शो-पीस बनकर रह गया है।

उक्त जेनरेटर ने शायद ही कभी डाकघर के लिए अपनी सेवा दी हो क्योंकि बताया जाता है कि सरकार द्वारा लाखों रुपए खर्च कर लगाया गया उक्त जेनरेटर अपनी सेवाएं देने से पहले ही खराब पड़ा खुले में धूल फांक रहा हैं। जानकारी के अनुसार होडल क्षेत्र के आस-पास के लगभग 9 गांवों का पैसों का लेन-देन होडल स्थित इस 'आधुनिक' डाकघर से ही होता है जिसमें गौडोता, मरौली, सौंध, खईका, बनचारी, आलीमेव, अंधोप आदि गांव शामिल हैं। विभागीय नियुक्ति के अनुसार होडल के डाकघर में 1 पोस्टमास्टर व 3 लिपिक होने चाहिए जबकि पिछले लगभग 3 माह से 9 गांवों की जनता के डाक विभाग से संबंधित कार्यो की जिम्मेदारी का ठेका डाकघर में कार्यरत मात्र दो ही डाककर्मियों को सौंपा हुआ है। बेराजगारों द्वारा नौकरी के फार्मो की रजिस्ट्री आदि करने के लिए डाकघर में कई- कई घंटे प्रतीक्षा करनी पडती है। ज्यादातर पोस्ट ऑफिस में कार्यरत कर्मचारी शाम को 7 बजे तक कार्य निबटाते हुए देखे जा सकते हैं जबकि उनकी ड्यूटी का समय सुबह 9 बजे से सांय 5 बजे तक का होता है।